भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1763
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

दूध और शहद उत्पादक सहकारी समितियाँ

1763 # श्री नरहरी अमीनः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा दूध और शहद उत्पादक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है;
(ख) यदि हां तो दूध तथा शहद उत्पादन करने वाली सहकारी समितियां को सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किए जा रहे है;
(ग) पिछले पांच वर्षों में इन सहकारी समितियों द्वारा दूध और शहद के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और
(घ) गुजरात में दूध तथा शहद उत्पादन करने वाली कुल कितनी सहकारी समितियां स्थापित है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): भारत सरकार डेयरी और शहद उत्पादक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है:

डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में :

i. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):
इस निधि का उद्देश्य मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु नए प्रसंस्करण सयंत्रों और विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना और यह सुनिश्चित करना कि डेयरी सहकारी समितियां लाभ के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धी बनी रहें। इस योजना का कार्यान्वयन अंतिम उधारकर्ता (EBs) के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी डेयरी निगम के द्वारा किया जा रहा है।

ii. डेयरी क्रियाकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता करना– कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन:
यह योजना उत्पादक संगठनों (POs) को कार्यशील पूँजी पर 2 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। ऋण चुकौती/ ब्याज सर्विसिंग अवधि के अंत में शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज सबवेंशन पर देय है।

iii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):

भाग'क' गुणवत्ता युक्त दुग्ध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक दुग्ध शीतन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और उसको सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। भाग 'ख (सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी -DTC) का उद्देश्य देश भर में डेयरी सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों द्वारा गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बनाना और सशक्त करना है।

शहद उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में:

i. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (FPOs): राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) ने इन समूहों या हब में क्षमता के अनुसार 100 शहद किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की सिफारिश की। 10,000 (FPOs) के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, 100 शहद FPOs को अनुबंध- I के अनुसार पंजीकृत किया गया है।

ii. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM):

इस योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और मूल्य संवर्धन पर जोर देकर "स्वीट रिवॉल्यूशन" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास करना है । NDDB मधुमक्खी पालन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सहकारी नेटवर्क का लाभ उठाती है और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी फसलोत्तर बुनियादी अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की स्थापना में सहायता करती है।

(ग): MoAFW के अनुसार, भारत ने 2022-23 के दौरान लगभग 1,42,000 मीट्रिक टन (दूसरा अग्रिम अनुमान) शहद का उत्पादन किया। IMARC (इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप) की रिपोर्ट के अनुसार, 2017-2022 के दौरान भारत का शहद बाजार 11.6% की CAGR से बढ़ा। देश में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में पिछले पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान लगभग 6% सालाना की वृद्धि हुई है।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में आर्गनाइज्ड डेयरी सहकारी समितियों की संख्या निम्नानुसार है:

डेयरी सहकारी समितियां :-

गुजरात में ऑर्गनाइज्ड डेयरी सहकारी समितियों की संख्या

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आर्गनाइज्ड डेयरी सहकारी समितियां (सं)	19,985	19,538	19,763	19,954	20,220

स्रोत: गुजरात दुग्ध संघ

शहद उत्पादक FPOs:-

गुजरात में स्थापित कुल 4 शहद उत्पादक FPOs की संख्या नवसारी, बनासकांठा, मेहसाणा और वलसाड प्रत्येक जिले में एक-एक है।

*****

अनुबंध- I

100 FPOs की राज्यवार सूची		
क्रम.सं.	**राज्य का नाम**	**FPOs की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	3
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	4
4	बिहार	5
5	छत्तीसगढ़	3
7	गुजरात	4
8	हरियाणा	2
9	हिमाचल प्रदेश	3
10	जम्मू और कश्मीर	4
11	झारखंड	3
12	कर्नाटक	4
13	केरल	2
14	मध्य प्रदेश	5
15	महाराष्ट्र	5
16	मणिपुर	2
17	मेघालय	3
18	मिजोरम	2
19	नागालैंड	2
20	ओडिशा	4
21	पंजाब	3
22	राजस्थान	5
23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	3
25	तेलंगाना	2
26	त्रिपुरा	1
27	उत्तर प्रदेश	16
28	उत्तराखंड	3
29	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	**100**